



मध्यप्रदेश शासन
पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग
मंत्रालय, वल्लभ भवन

क्रमांक / 4787 /NR-1/MGNREGS-MP/2016

भोपाल, दिनांक 25 /5/2016

प्रति,

01. कलेक्टर / जिला कार्यक्रम समन्वयक
02. मुख्य कार्यपालन अधिकारी / अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक

जिला—भोपाल, सीहोर, रायसेन, राजगढ़, विदिशा, नीमच, खंडवा, कटनी, शहडोल, उमरिया, अनूपपुर, टीकमगढ़, मुरैना, झाबुआ, मंदसौर, गुना, आगरा—मालवा, शाजापुर, भिंड, शिवपुरी, रतलाम, बैतुल, बुरहानपुर, इन्दौर, राजगढ़, रीवा, जबलपुर, सीधी, सागर, दमोह, सिंगरौली, पन्ना, सतना, डिन्डौरी, हरदा, देवास, सिवनी, श्योपुर, छतरपुर, धार, छिंदवाडा मध्यप्रदेश।

विषय :- मनरेगा योजना हेतु वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिये राशि उपलब्धता के संबंध में।

संदर्भ :- सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग नई दिल्ली का

D.O.No. J-11018/1/2/2015-MGNREGA-IV (Pt-3), दिनांक 11 अप्रैल, 2016.

—00—

विषयांतर्गत लेख है कि राज्य शासन वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए ग्राम पंचायतों द्वारा प्रस्तावित नरेगा सॉफ्ट में अपलोड 20.33 करोड़ मानव दिवस लेबर बजट अनुसार चालू वित्त वर्ष में ही प्रस्तावित लेबर बजट प्राप्त हो सके ताकि विगत वर्षों के लंबित सभी निर्माण कार्यों को पूर्ण किया जा सके एवं प्रदेश के सूखा प्रभावित 42 जिलों की 268 तहसीलों में 50 मानव दिवस का अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराकर सभी लक्ष्यों की पूर्ति करने हेतु भारत सरकार से सतत संपर्क कर प्रयासरत है।

इसी क्रम में भारत सरकार के संदर्भित पत्र के अनुसार राज्य सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2016-17 के लिए प्रस्तुत लेबर बजट से प्रसन्नता व्यक्त की है एवं प्रस्तुत बजट को वास्तविक मांग मान्य किया है। साथ ही विगत वर्षों के लंबित भुगतान एवं माह अप्रैल 2016 में योजना क्रियान्वयन हेतु भारत सरकार द्वारा आवश्यक राशि जारी कर दी गई है। राज्य में सूखे की स्थिति को दृष्टिगत रखते हुए विशेष ध्यान देकर मजदूरी की मांग अनुसार तेज गति से कार्य करने की आवश्यकता पर बल दिया है और इस बावत आश्वस्त किया है कि प्रभावी मनरेगा योजना के क्रियान्वयन में मंत्रालय ग्रामीण विकास विभाग भारत सरकार पूर्ण सहयोग के लिये तत्पर है।

अतः योजना क्रियान्वयन में किसी प्रकार की शीथिलता नहीं होनी चाहिए साथ ही गुणवत्तायुक्त परिसंपत्तियों का निर्माण किया जाना सुनिश्चित करे।

Deen

(अलका उपाध्याय)

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

क्रमांक / 4788 /NR-1/MGNREGS-MP/2016

भोपाल, दिनांक 25 /5/2016

प्रतिलिपि :-

संभाग आयुक्त संभाग (समस्त) की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

Deen

प्रमुख सचिव

म.प्र. शासन

पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग

एस. एम. विजयानंद
S. M. VIJAYANAND



सचिव
भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग
कृषि भवन, नई दिल्ली-110001
SECRETARY
Government of India
Ministry of Rural Development
Department of Rural Development
Krishi Bhawan, New Delhi- 110001
Tel: 91-11-23382230, 23384467
Fax: 91-11-23382408
e-Mail: secyrd@nic.in

No. 424 PA/DC & ACS/1
Date 28/04/16

मुख्य सचिव कार्यालय
CS/Gen-Col/ 2962
Date 22-4-16

D.O.No.J-11018/1/2/2015-MGNREGA-IV(Pt-3)

April 11, 2016

Dear Sir,

I am happy to inform you that based on the Action Plan of your State on MGNREGS for 2016-17 funds have been released for clearing the pending wage liability of 2015-16 and for running the programme during April, 2016.

2. Taking into account the drought conditions in your State, may I request you to intensify the implementation of MGNREGS with special focus on drought affected areas? It may kindly be ensured that while providing employment, assets which combat drought may be given top priority.

3. Let me also mention that the agreed to Labour Budget for 2016-17 does not imply that work cannot be provided beyond the Labour Budget if there is genuine demand for work.

4. Let me assure you full support of the Ministry of Rural Development for effective implementation of MGNREGS in your State.

With regards,

AE/Plan
28/4/16

Yours sincerely,

(S.M. Vijayanand)

Shri Anthony J.C. Desa,
Chief Secretary,
Government of Madhya Pradesh,
Bhopal - 462004.

20 APR 2016
ACS P&R.D.

1229-
28/4/16
ACS
we need to see
for more funds
an

Comm(NREGS)
Re. but update for
been more funds
20 moved today.
25.04.16